शीर्षप्राथमिकता
संख्या–2160 / सत्तर–3–2022

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 08 अगस्त, 2022

विषयः– स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2022 मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूचना अनुभाग–2 के पत्र सं0–05 / 2022 / 464 / उन्नीस–2–2022–1061 / 85, दिनांक 06.08.2022, (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 76 वां स्वाधीनता दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी, परन्तु आकर्षक ढंग से मनाया जायेगा।

2– इसी कम में प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों / कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस समारोह–2022 के अन्तर्गत आयोजित होने वाले कार्यकमो को सफल बनाते हुए निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चत की जाय।

(1) 15 अगस्त को प्रातः 8:00 बजे सरकारी तथा गैर सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तथा झण्डा–अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बांध कर उसे फहराया जा सकता है।

(2) आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु 15 अगस्त को समस्त सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक / औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि खुले रहेंगे तथा इन स्थलों पर खादी निर्मित राष्ट्रध्वज सम्मानपूर्वक फहराया जाए।

(3) उक्त सभी स्थलों पर इस राष्ट्रीय पर्व का उत्साह, उल्लास एवं उमंग के साथ समारोहपूर्वक आयोजित किया जाए, जिसमें राष्ट्रगान के साथ ही देशभक्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकम सम्मिलित हों। इन कार्यकमों के माध्यम से राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना की संचार किया जाए।

(4) इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ–निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिकता सौहार्द की भावना की बलवती बनाने पर जोर दिया जाये तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ–साथ लोगों की पराम्परागत एकता प्रदर्शित करने के लिए मानव–श्रखला बनाने पर भी विचार किया जाए।

(5) एन0एस0एस0 के माध्यम से प्रभात फेरियाँ निकाली जाएं जिसमें झण्डा गीत एवं अन्य राष्ट्रभंक्ति के गीतों का गायन किया जाए।

(6) उच्च शिक्षण संस्थानों में इस अवसर पर ऐसे कार्यकमों का आयोजन किया जाए, जिसमें राष्ट्रगान 'जन–गण–मन' का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता–संग्राम का इतिहास बताया जाय तथा देश के लिए शहीद हुए ज्ञात–अज्ञात विशेषकर स्थानीय देशभक्तों के जीवन के प्रेरक–प्रसंग दोहराये जायें, जिसमें उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देशप्रेम की

अति आवश्यक
1. सम-वयक N.S.S.
2. प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त संबद्ध महाविद्यालय
कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
09/8/22
कुलसचिव

Scanned with CamScanner

भावना जागृत करने वाले नाटक, विचार–गोष्ठी, वाद–विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबन्ध लेखन से सम्बन्धित प्रतियोगिताएं भी आयोजित करायी जाय।

(7) राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक 'राष्ट्रीय ध्वज' के महत्व के बारे में आगजन को बताया जाये। वरिष्ठ साहित्यकारों/लखकों/गीतकारों को आजादी की लड़ाई, तिरंगा की यात्रा के बारे में लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(8) देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह स्वतंत्रता दिवस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। अतएव दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह अवधि में समस्त सरकारी कार्यालयों–भवनों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एतिहासिक स्मारकों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

(9) सम्पूर्ण सप्ताह में जनसहभागिता के साथ प्रेक्षागृहों, शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक आयोजन एवं कवि सम्मेलन आदि आयोजित करायें जाएं। 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान हर दिन देशभक्ति के अलग–अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। स्कूलों में झण्डा–गीतों का गायन हो।

(10) स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2022 की रात्रि में सरकारी कार्यालय–भवनों तथा अंन्य इमारतों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाये।

(11) आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रमों के सफल कियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाये तथा समस्त सरकारी/गैर सरकारी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के स्थल पर पोस्टर/बैनर एवं स्टैण्डी अवश्य लगाये जायें।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह–2022 में आयोजित होने वाले कार्यक्रमो को कार्यकम को सफल बनाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या–3160 (1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
(2) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
(3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
(4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner

386/2022

महत्वपूर्ण

संख्या- 05 /2022/464/उन्नीस-2-2022-1061/85

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 अगस्त, 2022

विषयः स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2022 मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 76वां स्वाधीनता दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी, परन्तु आकर्षक ढंग से मनाया जायेगा।

2. अवगत हैं कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे वर्ष भर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में गरिमामय ढंग से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक **'स्वतंत्रता सप्ताह'** एवं दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2022 तक **'हर घर तिरंगा कार्यक्रम'** आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना तथा स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार गरिमामय ढंग से आयोजित किया जाए।

3. स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2022 के सम्बन्ध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किन्तु यदि आवश्यक समझें तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

(1) 15 अगस्त को प्रातः 8:00 बजे सरकारी तथा गैर-सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तथा झण्डा-अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़ियां बांध कर उसे फहराया जा सकता है।

(2) आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु 15 अगस्त को समस्त सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि खुले रहेंगे तथा इन स्थलों पर खादी निर्मित राष्ट्रध्वज सम्मानपूर्वक फहराया जाए।

(3) उक्त सभी स्थलों पर इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह, उल्लास एवं उमंग के साथ समारोहपूर्वक आयोजित किया जाए, जिसमें राष्ट्रगान के साथ ही देशभक्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सम्मिलित हों। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना का संचार किया

Scanned with CamScanner

जाए।

(4) इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ-निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को बलवती बनाने पर जोर दिया जाये तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ-साथ लोगों की परम्परागत एकता प्रदर्शित करने के लिए मानव-शृंखला बनाने पर भी विचार किया जाए।

(5) सभी विद्यालयों, मुहल्लों से प्रभात फेरियाँ निकाली जाएं जिसमें झण्डा गीत एवं अन्य राष्ट्रभक्ति के गीतों का गायन किया जाए।

(6) समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये, जिसमें राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास बताया जाय तथा देश के लिए शहीद हुए ज्ञात-अज्ञात विशेषकर स्थानीय देशभक्तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंग दोहराये जायें, जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देशप्रेम की भावना जागृत करने वाले नाटक, विचार-गोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबन्ध-लेखन से सम्बन्धित प्रतियोगिताएं भी यथा-सम्भव आयोजित करायी जायें। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

(7) शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किये जायें।

(8) स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में किसान, मजदूर, छात्र, युवा आदि सभी नागरिकों को सम्मिलित करते हुए पूरे उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए।

(9) स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु शासन के खेल विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

(10) स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पूर्व युवक मंगल दलों व महिला मंगल दलों द्वारा अमृत मिनी मैराथन का आयोजन किया जाए।

(11) प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र पर न्यूनतम 75 किसानों को पौध व तिरंगे भेंट किये जायें।

(12) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के अमृत सरोवरों पर ध्वजा-रोहण के साथ-साथ वृक्षारोपण, प्रकाश व्यवस्था, स्वाधीनता संग्राम के महत्व पर संगोष्ठी तथा देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित की किए जाएँ।

(13) ग्राम सचिवालयों एवं अमृत सरोवरों पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ।

4. अपरान्ह में परम्परागत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाये जिसमें -

(1) स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जन-साधारण को यह भी याद दिलाया जाये कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष करके, अपना सब कुछ न्यौछावर कर जो राजनीतिक स्वाधीनता हासिल की थी, उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता लाने का दायित्व विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जन-साधारण को बताया जाये कि सभी समुदायों के महापुरूषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाई-चारे व इंसानियत पर बल दिया है। इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाये, ताकि समाज में इन्सान और इन्सानियत का महत्व बढ़े। स्वतंत्रता सप्ताह की अवधि में गांव व नगर में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और पार्कों को सजाया जाए।

Scanned with CamScanner

(2) राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक **'राष्ट्रीय ध्वज'** के महत्व के बारे में आमजन को बताया जाये। वरिष्ठ साहित्यकारों/लेखकों/गीतकारों को आजादी की लड़ाई, तिरंगा की यात्रा के बारे में लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(3) पंथ-निरपेक्षता की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाये कि राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रेम, सद्भावना, मेल-जोल एवं एक-दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरूषों का आदर करने से होता है।

(4) इस समारोह में यथासम्भव स्थानीय स्वाधीनता संग्राम सेनानी/सेनानियों तथा सेना अथवा पुलिस बल के शहीदों के परिवार के सदस्यों को ससम्मान आमंत्रित किया जाए।

5. 15 अगस्त, 2022 को ब्लाक, तहसील तथा जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाये। श्रेयस्कर होगा कि इन समारोहों का आयोजन उन्हीं स्थानों पर किया जाये, जहां सन् 1947 में स्वाधीनता मिलने पर जन-समुदाय ने आह्लादित एवं रोमांचित होकर यह उत्सव मनाया था।

6. देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर यह स्वतंत्रता दिवस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। अतएव दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक स्वतंत्रता सप्ताह अवधि में समस्त सरकारी कार्यालयों-भवनों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एतिहासिक स्मारकों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

7. स्वतंत्रता सप्ताह की दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 की अवधि में प्रभात-फेरियां निकाली जाएं।

8. स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर पुलिस बैण्ड का वादन कराया जाए।

9. सम्पूर्ण सप्ताह में जनसहभागिता के साथ प्रेक्षागृहों, शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रभक्ति पूर्ण सांस्कृतिक आयोजन एवं कवि सम्मेलन आदि आयोजित करायें जाएं। 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान हर दिन देशभक्ति के अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। स्कूलों में झण्डा-गीतों का गायन हो।

10. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2022 की रात्रि में सरकारी कार्यालय-भवनों तथा अन्य इमारतों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाये।

11. आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये तथा समस्त सरकारी / गैर सरकारी / निजी संगठनों के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के स्थल पर पोस्टर / बैनर एवं स्टैण्डी अवश्य लगाये जायें।

12. जागरूकता प्रसार के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक बस स्टैण्ड से एवं मेट्रो कारपोरेशन द्वारा मेट्रो कोचेज एवं स्टेशन से लोगों को उक्त अवधि में हर घर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से नियमित उदघोषणा कराई जाए।

13. स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर अधिकाधिक जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थाओं, समूहों तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाये जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप

Scanned with CamScanner

कार्यक्रम आयोजित करने की सदिच्छा व्यक्त करते हैं।

14. हर घर तिरंगा कार्यक्रम में अपने-अपने घरों पर फहराये तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन के सेल्फी पोर्टल http://harghartirangaup.org की वेब साइट पर पोस्ट हेतु आम नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए।

15. विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं से जन-मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाये। साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाय।

16. प्रदेश सरकार **'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास'** की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, समर्थ, समावेशी तथा राष्ट्रवादी प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं उपेक्षित वर्ग का समावेश करते हुए प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए **'साफ नीयत, सही विकास'** के संकल्प को साकार कर रही है। यह भावना सभी आयोजनों में स्वतः परिलक्षित हो।

17. राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उसकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। वर्तमान सरकार **'सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास'** के संकल्प के साथ सभी के हित से जुड़े निर्णय ले रही है, जिससे विकास के नये रास्ते खुलेंगे और प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका **संलग्न परिशिष्ट** में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जनसभाओं में जनमानस को अवगत कराया जाए।

18. यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना एवं एकता से ही प्रगति कर सकता है। वर्तमान सरकार सुशासन, सुरक्षा एवं विकास के रास्ते पर चलते हुए कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाए।

संलग्नक - परिशिष्ट

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 06-08-2022 15:04:57
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या- 05 /2022/464(1) /उन्नीस-2-2022-1061/85 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि/ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रदेश के मा0 उप मुख्यमंत्री/समस्त मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य

Scanned with CamScanner

मंत्रीगण के निजी सचिवों को मा0 महानुभवों के सूचनार्थ।

2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।

3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।

4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।

7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उ0प्र0।

8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।

10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।

12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्त्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रम

1. जनसमस्या निवारणः

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित **"जनता दर्शन"** में प्रदेश के कोने-कोने से आये पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रिवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत प्राप्त कुल 3,62,73,916 संदर्भों में से 3,58,06,839 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर जनसामान्य की समस्याओं/शिकायतों का निस्तारण करें। तहसीलों में **'सम्पूर्ण समाधान दिवस'** का आयोजन अब प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा **'थाना दिवस'** दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों के निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ की

Scanned with CamScanner

गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, मा0 मंत्री समूहों द्वारा अलग-अलग जनपदों व मण्डलों का भ्रमण कर 'सरकार आपके द्वार' के अनुरूप जनता से संवाद स्थापित कर जनसमस्याओं के समाधान तथा जनआकांक्षाओं के दृष्टिगत विकास कार्य संचालित करने के विशेष प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं।

2. आस्था को नमन:

(1) कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 01 लाख रुपये प्रति यात्री की गई। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर/चार धाम यात्रियों की सुविधा हेतु 68.46 करोड़ रुपये की लागत से बने भवन का मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया।

(2) सिंधु दर्शन का अनुदान 20 हजार रुपया प्रति यात्री किया गया।

(3) जनपद वाराणसी में वैदिक सांइस सेन्टर की स्थापना। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तारीकरण / सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

3. कानून व्यवस्था:

(1) प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी।

(2) प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु साइबर क्राइम थाना लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना। प्रदेश के सभी 1,531 थानों में साइबर हेल्पडेस्क की स्थापना। प्रदेश में नये बनने वाले यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज लखनऊ के तहत सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना होगी।

(3) प्रदेश की कारागारों में मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के प्रयोग पर 3 से 5 वर्ष की सजा तथा 50 हजार रुपये अथवा दोनों से दण्डित करने का प्रावधान।

(4) 112 यू0पी0 परियोजना को और अधिक जनपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढ़ोतरी कर कई नयी परियोजनायें जोड़ी गई हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वीमेन पावर लाइन 1090, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का एकीकरण।

(5) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन। मिशन शक्ति अभियान चलाकर कार्यवाही की गई।

(6) सुरक्षा व्यवस्था हेतु सभी कारागारों में 3,200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित।

(7) हड़ताल, बन्दी, दंगों, लोक अशांति के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हिंसात्मक कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तथा लोक एवं निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली के लिए लखनऊ एवं मेरठ मण्डल में दावा अधिकरण का गठन।

(8) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से **उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स** नामक नये सुरक्षा बल का गठन।

(9) **ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली** के उपयोग में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।

(10) प्रदेश के 25 कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके तथा उनके सहयोगियों द्वारा

Scanned with CamScanner

आपराधिक कृत्य से अर्जित की गई सम्पतियों में लगभग 675 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध सम्पतियों की ध्वस्तीकरण/जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त 8 अन्य कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध 40 करोड़ से अधिक के मूल्य की अवैध सम्पतियों की जब्तीकरण की गई। वर्तमान सरकार के 100 हेतु निर्धारित कार्य योजना में अब तक 62 माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

(11) चिन्हित प्रमुख 62 माफियाओं व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों से अब तक 896 के विरुद्ध कार्यवाही कर 405 अभियोग पंजीकृत किये गये, 431 गैंग सदस्यों/सहयोगियों की गिरफ्तारी की गयी, 178 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट, 884 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, 13 के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही की गयी।

(12) नवम्बर, 2019 से अब तक माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों की कुल 1812 करोड़ 47 लाख 89 हजार रु0 से अधिक की सम्पतियां जब्त की गयी। वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में गैंगेस्टर एक्ट में 500 करोड़ रु0 वसूली के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 844 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

(13) प्रत्येक थाने पर टॉप-10 अपराधियों के चिन्हीकरण के तहत 15 हजार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही का लक्ष्य निर्धारित कर कृत कार्यवाही से 16,158 टॉप-10 अपराधी चिन्हित किये गये, जिनके विरुद्ध अब तक कुल 83,721 अभियोग पंजीकृत कराये जा चुके हैं तथा 648 करोड़ रुपये की सम्पति भी जब्त की जा चुकी है।

(14) पुलिस विभाग में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के 100 दिन के अभियान के तहत 10 हजार पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले ही शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 9534 युवाओं को उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर चयनित किया गया तथा 500 मृतक आश्रितों की भर्ती की गयी है।

(15) अग्निशमन वाहनों सहित 25 नवनिर्मित केन्द्रों को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता को समर्पित किया गया। अग्निशमन एवं जीवन संरक्षण हेतु 815 ब्लॉकों में 90,851 स्वयंसेवी प्रशिक्षित।

(16) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम-2021 लागू। धार्मिक स्थलों से 74,385 लाउडस्पीकर हटाये गये।

4. <u>किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले:</u>

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कुल 2.60 करोड़ किसानों को अब तक कुल 48311 करोड़ रु0 की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गयी।

(2) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में माह मार्च, 2022 तक 249223 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराये गये, जिसमें 74 प्रतिशत पुरुष एवं 26 प्रतिशत महिला लाभार्थी हैं।

(3) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 281.25 लाख बीमित कृषकों द्वारा 197.19 लाख है0 क्षेत्र में बीमा कराया गया, जिसमें 27.59 लाख कृषकों को रुपये 3,074.60 करोड़ क्षतिपूर्ति का भुगतान।

(4) किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार द्वारा कुल 2,90,426 स्प्रिंकलर सेट का वितरण।

Scanned with CamScanner

(5) बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए खेत-तालाब योजना के तहत अब तक 27,316 खेत-तालाबों का निर्माण। बुंदेलखण्ड क्षेत्र के किसानों को विभिन्न फसलों के बीजों पर 80 प्रतिशत अनुदान तथा रबी में समस्त योजनाओं के अंतर्गत समस्त प्रकार के बीजों के मूल्य का 50 प्रतिशत समस्त जनपदों में अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया गया।

(6) प्रदेश में जहां सिंचाई के साधन कम हैं अथवा विद्युत आपूर्ति नहीं है, उन क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टैइक इरिगेशन पम्प के तहत कुल 26,407 सोलर पम्पों की स्थापना।

(7) बुन्देलखण्ड के समस्त 47 विकास खण्डों में 50 हे0 आकार के मिशन प्राकृतिक खेती हेतु 10 क्लस्टर का क्रियान्वयन।

(8) बंजर, बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु रु0 602 करोड़ का प्राविधान। 336 कृषि कल्याण केन्द्रों में 184 केन्द्र क्रियाशील।

(9) किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए अब तक कुल 300.28 लाख कुन्तल बीजों का वितरण तथा 440.60 लाख मी0 टन उर्वरकों का वितरण। अब तक कुल 88,347.66 मी0 टन/किली0 कृषि रक्षा रसायनों का वितरण।

(10) फसली ऋण के तहत मार्च 2022 तक कुल 5,10,992.14 करोड़ रुपये का वितरण।

(11) जनपद जालौन में 40 हजार कुन्तल वार्षिक क्षमता के बीज विधायन केन्द्रों की स्थापना।

(12) राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वाधिक तिलहन उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ रुपये का 'कृषि कर्मण पुरस्कार' तथा देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु रुपये 1 करोड़ का प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त। वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत।

(13) सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को अल्पकालीन ऋण वितरण के अन्तर्गत माह 30 जून, 2022 तक 5,313.40 करोड़ रु0 का ऋण वितरित। दीर्घकालीन ऋण के तहत इस वित्तीय वर्ष में जून, 2022 तक 36.17 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2021-22 में 4,78,226 मीट्रिक टन उर्वरक तथा 76 कुन्तल बीज का वितरण। ग्रामीण गोदाम योजना के अंतर्गत 100 मी0 टन के 100 गोदामों का निर्माण पूर्ण।

(14) केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के तहत मण्डी परिसरों के बाहर के व्यापार को पूरी तरह लाईसेंस व मण्डी शुल्क से मुक्त। इससे किसान अपना सामान कहीं भी और किसी भी व्यापारी को तत्काल बेंच सकते हैं। 27 प्रमुख मण्डी समितियों को आधुनिक किसान मण्डी के रूप में विकसित करने का कार्य अंतिम चरण में। 54 ग्रामीण हॉट का निर्माण। ई-मण्डी योजना लागू।

(15) मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत 67119 से अधिक कृषकों को 110.40 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान सहायता राशि वितरित।

5. <u>गन्ना किसानों को सुविधाएं:</u>

(1) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में **प्रथम स्थान पर।**

(2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,77,508 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।

(3) गन्ना उत्पादकता में 9.93 टन प्रति हे0 की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि।

(4) प्रदेश में 22.70 लाख हे0 क्षेत्र में गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25

Scanned with CamScanner

प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

(5) ई0आर0पी0 के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल 'caneup.in' एवं 'E-Ganna' ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेन्डर पर्ची एवं भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को उपलब्ध। गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु ऐस्को एकाउण्ट की व्यवस्था लागू।

(6) बन्द पड़ी चीनी मिल पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) व रमाला (बागपत) में 5,000 टी0सी0डी0 क्षमता की 02 नई चीनी मिल का निर्माण व विस्तार, 27 मेगावॉट क्षमता के विद्युत संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण।

(7) ऑनलाइन खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति जारी। प्रथम बार 282 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाईसेंस निर्गत। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,227.55 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश तथा 41,735 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

(8) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 3,003 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन। 58,905 ग्रामीण महिला उद्यमी पंजीकृत। 3239.40 लाख रुपये का अनुदान समूहों को वितरित।

6. आबकारी विभाग:

(1) आबकारी विभाग प्रदेश के कर राजस्व में योगदान करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है। इस वर्ष 42,500 करोड़ रु0 राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया है। इसके सापेक्ष रू0 8,571 करोड़ राजस्व अर्जित।

(2) शीरा उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।

(3) इस वर्ष 03 नई आसवनियां स्थापना की अनुमति। इससे 793.37 करोड़ का निवेश तथा 3,600 नये रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

(4) एथेनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एथेनॉल आपूर्तिकर्ता राज्य बन गया है। विगत वर्ष 115 करोड़ ब0ली0 एथेनॉल का उत्पादन किया गया। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

7. खाद्य एवं रसद विभाग:

(1) **मूल्य समर्थन योजना** के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2022-23 में 2015 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए गेहूँ किसानों से क्रय किया गया।

(2) मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीफ वर्ष 2021-22 में 11,01,945 कृषकों से 65.53 लाख मी0टन धान की खरीद की गई तथा किसानों को 12,648.30 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

(3) मक्का क्रय हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मक्के का निर्धारित समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 704 किसानों से 2,762.85 मी0टन मक्का क्रय करते हुए रुपये 5.15 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है।

(4) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के समस्त अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित।

Scanned with CamScanner

(5) उचित दर की दुकानें अब कॉमन सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित। बेघर एवं कचरा उठाने वाले 780 परिवारों को राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न वितरित।

(6) 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत मई 2020 से अब तक अन्य राज्यों के 42,049 राशन कार्ड धारकों को उ0प्र0 से तथा उ0प्र0 के 11,44,612 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया।

8. <u>उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण</u>:

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत कुल 1213 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें पूंजी निवेश रुपये 6,236.23 करोड़ तथा कुल लगभग 47,672 रोजगार का सृजन होगा। इसके सापेक्ष अब तक 572 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें रु0 1,682.41 करोड़ का निजी पूंजी निवेश और 43,030 रोजगार सृजन हुआ।

(2) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 1,874 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कार्यशील पूंजी एवं छोटे औजारों की खरीद हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राज्य शहरी आजीविका मिशन को रु0 479.85 लाख की धनराशि अवमुक्त।

(3) एकीकृत बागवानी विकास मिशन में निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा स्थापित 125 शीतगृह, 21 राइपनिंग चेम्बर, 03 मिनिमल प्रोसेसिंग इकाई, 587 पैक हाउस, 197 प्याज भण्डारगृहों एवं 132 लो कास्ट प्रिजर्वेशन इकाई की स्थापना के लिए रु0 181.71 करोड़ का अनुदान।

(4) देश के कुल आलू उत्पादन का 30 से 35 प्रतिशत आलू उत्तर प्रदेश में होता है। हापुड़ एवं कुशीनगर में दो आलू आधारित सेन्टर आफ एक्सीलेंस भवन का शिलान्यास तथा 02 नवनिर्मित मिनी सेन्टर आफ एक्सीलेंस फतेहपुर व रामपुर का लोकार्पण।

9. <u>उद्योग</u>:

(1) **उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट** के तहत तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी 03 जून 2022 को आयोजित, जिसमें 80 हजार करोड़ रु0 से अधिक की 1,406 परियोजनाओं का शुभारम्भ। इससे लगभग 05 लाख प्रत्यक्ष तथा लगभग 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।

(2) वर्ष 2020-21 में बी0आर0ए0पी0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी में स्थान प्राप्त। विभिन्न लाइसेंस स्वीकृतियां, एन0ओ0सी0 आदि के संबंध में 72 घंटे में एक्नॉलेजमेंट प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 29 विभागों की लगभग 352 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(3) उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कोरिडोर परियोजना हेतु 5,000 है0 भूमि की अवश्यकता होगी जिसमें से 1547 है0 भूमि का अधिग्रहण कार्य पूर्ण।

(4) उद्योगों हेतु लैण्ड बैंक का सृजन के अंतर्गत प्रदेश में पूर्व से ही 20,000 एकड़ का औद्योगिक भूमि बैंक उपलब्ध है। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में निजी औद्योगिक इकाईयों की पात्रता सीमा 100 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ कर दी गई है।

(5) **एक जनपद-एक उत्पाद** कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से राज्य के निर्यात में 80 प्रतिशत की वृद्धि। 2017-18 में निर्यात 88,967 करोड़ रुपये था जो 2021-22 में बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपये हो गया। 70 हजार ओडीओपी कारीगरों को प्रशिक्षित कर टूलकिट वितरित। 8468 लाभार्थियों को रु0 28,393.89 लाख मार्जिन मनी वितरित। 1,09,415 व्यक्तियों को रोजगार

Scanned with CamScanner

सृजित कराया गया। ओडीओपी ई-कामर्स odopmart.com पोर्टल पर 20 हजार से अधिक उत्पाद बेचे जा रहे हैं। Flipkart पर 1600 करोड़ से अधिक उत्पादों का विक्रय।

(6) दिनांक 30.06.2022 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मेगा लोन मेला का शुभारम्भ। मेले के माध्यम से 1,90,000 लाभार्थियों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत रु0 16,000 करोड़ का ऋण वितरित। वर्तमान वितीय वर्ष में अब तक 1,20,217 इकाईयां भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत।

(7) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1,43,412 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए रोजगार का सृजन। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 हजार हस्तशिल्पियों/पारम्परिक कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(8) भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत जनपद-आगरा, कानपुर नगर व गोरखपुर में फ्लेटेड फैक्ट्री काम्पलेक्स स्थापित करने संबंधी परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है। जिनमें आगरा एवं कानपुर नगर की परियोजनाएं शिलान्यास हेतु तैयार हैं।

(9) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 14,850 लाभार्थी लाभान्वित। 1,18,800 रोजगार का सृजन। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 17,679 व्यक्ति लाभान्वित। 1,41,432 रोजगार का सृजन। अनुसूचित जाति/जनजाति के 33855, अन्य पिछड़ा वर्ग के 9,375 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया गया। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 13,124 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

10. <u>सूचना प्रौद्योगिकीः</u>

(1) सरकार द्वारा नयी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 अधिसूचित। उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अंतर्गत 04 डाटा सेन्टर पार्क्स तथा एक डाटा सेन्टर इकाई की स्थापना से रु0 16,147 करोड़ के 460 मेगावाट क्षमता के निवेश प्रस्तावों पर अनुमोदन कर लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया गया।

(2) स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 10,88,791 टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित। आईआईटी कानपुर परिसर में ड्रोन सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।

(3) 03 जून, 2022 को आयोजित ग्राउण्ड ब्रेकिंग समिट-3.0 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हेतु रु0 23,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं में निवेश।

(4) विदेशी कम्पनियों हेतु ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित। 3,000 करोड़ से अधिक निवेश के साथ ताइवान की सदस्य इकाईयों द्वारा उत्पादन इकाईयां स्थापित होंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र भारत में एक इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण हब के रूप में प्रतिष्ठित।

(5) उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास का संकल्प।

(6) उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 प्रख्यापित। इसके तहत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने का संकल्प। 6,500 से अधिक स्टार्टअप उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के साथ पंजीकृत हैं। राज्य भर में 48 इन्क्यूबेटर कार्यरत।

Scanned with CamScanner

(7) भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग्स फ्रेमवर्क 2020-21 के अंतर्गत उ0प्र0 राज्य ने उल्लेखनीय गुणात्मक सुधार करते हुए लीडर्स की श्रेणी में स्थान अर्जित किया।

11. <u>जी0एस0टी0:</u>

(1) वर्ष 2022-23 माह जून, 2022 तक के लक्ष्य 31,786.65 करोड़ रुपये के सापेक्ष 32,386.36 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष से अधिक है।

(2) जी0एस0टी0 में समाधान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3.38 लाख व्यापारी लाभान्वित।

(3) उ0प्र0 में जी0एस0टी0 में एक्टिव पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.52 लाख हो गई, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है।

(4) ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना 2020 व 2021 के अंतर्गत 28,642 व्यापारी लाभान्वित तथा रुपये 245.44 करोड़ की बकाया धनराशि जमा हुई।

(5) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्ष 2017-18 से अब तक 778 व्यापारी लाभान्वित।

12. <u>नगर विकास:</u>

(1) स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत **'इंडिया स्मार्ट सिटी आवार्ड कांटेस्ट'** में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान। प्रदेश के 05 शहर देश के टॉप 20 शहरों में शामिल।

(2) **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** के तहत 17.70 लाख स्वीकृत आवासों में से 11.77 लाख आवास पूर्ण।

(3) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 8.55 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित।

(4) **अमृत योजना** के अन्तर्गत प्रदेश के 60 शहर आच्छादित। योजनान्तर्गत पेयजल की 124 तथा सीवरेज की 60 परियोजनाएं पूर्ण। अमृत-2.0 में 8,000 करोड़ रुपये की 105 परियोजनाएं स्वीकृत।

(5) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 8.98 लाख व्यक्तिगत शौचालय, 69,265 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय एंवं प्रदेश के समस्त निकायों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का निर्माण।

(6) गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज में 650 टी0पी0डी0 के सी0 एण्ड डी0 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लाण्ट की प्रथम बार स्थापना।

(7) नगरीय परिवहन को सुगम बनाने के तहत 14 नगरों में 446 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन।

(8) जनसामान्य की सुविधा के लिए 60 शहरों में ई-नगर सेवा लागू।

(9) नगरीय निकायों में सुविधाओं एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए प्रदेश स्तरीय डीसीसीसी व्यवस्था की नगरीय निकाय निदेशालय में स्थापना।

(10) लोगों की समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीकी आधारित 'सम्भव' पोर्टल की व्यवस्था तथा प्रदेशव्यापी टोल फ्री नं0 1533 शुरू किया गया।

13. <u>जलशक्ति:</u>

(1) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बुन्देलखण्ड सहित

Scanned with CamScanner

संचालित 20 परियोजनाएं पूरी। 21.42 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित, 45 लाख कृषक लाभान्वित।

(2) 46 वर्षों से लम्बित बाणसागर नहर परियोजना पूरी करायी गयी। इसका लोकार्पण मा0 प्रधानमंत्री जी ने 15 जुलाई 2018 को किया। इस परियोजना से मिर्जापुर एवं प्रयागराज जनपदों की 1,50,132 हे0 भूमि सिंचित हो रही है और 1.70 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

(3) बबीना ब्लाक जनपद झांसी के 15 ग्रामों में रु0 246.85 करोड़ की लागत से सिंचाई परियोजना पूर्ण, परियोजना से 4,400 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन तथा 5,240 कृषक लाभान्वित।

(4) रु0 149.60 करोड़ की लागत से जनपद कानपुर देहात की उमरहट पम्प नहर परियोजना द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण, परियोजना से 19,630 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन, जिससे 1.97 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

(5) वर्ष 2022-23 में 11 परियोजनाएं पूर्ण करने का लक्ष्य।

(6) नहरों की सफाई अभियान के अंतर्गत 2021-22 में 50,961.73 कि0मी0 सिल्ट सफाई, जबकि 2022-23 में अब तक 1,933.23 किमी0 सिल्ट सफाई की गई।

(7) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

(8) वर्ष 2022-23 में 222 बाढ़ परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 62 परियोजनाएं पूर्ण की गई।

(9) 350 करोड़ रुपये की लागत से 25,050 पुल-पुलियों का जीर्णोद्वार, पुनर्निर्माण व नवनिर्माण का कार्य पूर्ण।

(10) विगत पांच वर्षों में रु0 786.23 करोड़ की लागत से 7,523.65 किमी0 लम्बाई की नहर पटरियों को गड्ढामुक्त/नवीनीकृत किया गया।

(11) प्रदेश में 6,000 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण 1,960 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण, 1,045 असफल राजकीय नलकूपों पुनर्निर्माण किया गया है।

14. <u>नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्तिः</u>

(1) नमामिगंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत 47 सीवरेज परियोजनायें लागत रु0 11,071.63 करोड़ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। 27 परियोजनाएं पूर्ण, 18 परियोजनायें निर्माणाधीन तथा 02 परियोजनायें प्रक्रियाधीन।

(2) औद्योगिक उत्प्रवाह शोधन संबंधी प्रदेश के पांच नगरों में 05 परियोजनायें एन0एम0सी0जी0 द्वारा स्वीकृत। 69 घाट एवं 13 शवदाह गृह का निर्माण। वाराणसी नगर में 08 कुण्डों के पुनरूद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण। 87 घाटों की सफाई का कार्य।

(3) कानपुर के 128 वर्ष पुराने सीसामऊ नाले को टेप कर गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण को समाप्त किया गया है। इससे गंगा नदी के जल गुणवत्ता में सुधार आया है।

(4) अयोध्या में पवित्र नदी सरयू में गिरने वाले सभी नालों को टैप कर पवित्र नदी सरयू की गुणवत्ता में सुधार लाया गया।

(5) विगत 100 दिनों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 574 गांवों में पाइप पेयजल योजनाएं पूरी करायी गईं। इनमें बुन्देलखण्ड/विंध्य क्षेत्र की 64 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं से

Scanned with CamScanner

3.76 लाख घरों को पानी के कनेक्शन दिये गये। विंध्य क्षेत्र में दिसम्बर, 2022 तक 6.5 लाख से अधिक फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन देने का लक्ष्य, इससे 40 लाख से अधिक आबादी को शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा।

(6) भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 26 विकास खण्ड भूजल प्रबंधन में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से चयनित।

(7) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 4,88,851 निःशुल्क बोरिंग, गहरी बोरिंग 4,064 व 12,007 मध्यम बोरिंग पूर्ण। 607 सामूहिक नलकूप, 501 तालाबों व 718 चेकडैम का निर्माण, 1,256 ब्लास्ट कूप निर्माण करते हुए 9,98,653 हे0 अतिरिक्त भूमि सिंचन क्षमता का सृजन। मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में 93,255 मानव दिवस सृजित किया गया।

15. <u>अवस्थापना सुविधाओं का विकास:</u>

(1) **पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे:** प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी0 लम्बे 06 लेन चौड़े (08 लेन विस्तारणीय) एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 नवम्बर, 2021 को लोकार्पण किया गया। यातायात संचालित। एक्प्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(2) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे: 296 किमी0 लम्बे एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 जुलाई, 2022 को लोकार्पण किया गया। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(3) **गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे** परियोजना का 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण। निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु भूमि चिन्हित।

(4) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने हेतु गाजीपुर से बलिया होते हुए माझी घाट तक **बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे** बनाये जाने का निर्णय।

(5) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बे रू0 36,230 करोड़ लागत से बन रहे **गंगा एक्सप्रेस-वे** के निर्माण हेतु 94 प्रतिशत से अधिक भूमि का क्रय/अधिग्रहण।

(6) उत्तर प्रदेश में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चयनित सभी 06 नोड्स अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में 1,599 हे0 से अधिक भूमि क्रय/पुनर्गहण की जा चुकी है। 91 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित। 11 हजार करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित।

(7) ग्रेटर नोएडा में 5,000 हे0 में विकसित हो रहे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तरी भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। राज्य सरकार ने प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 06 किलोमीटर दूर 1,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फिल्म सिटी की अवस्थापना विकास कार्य प्रगति पर। प्रदेश में अब तक क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़कर 03 (लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर), तथा क्रियाशील डोमेस्टिक एयरपोर्ट की संख्या 06 (गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन एवं बरेली) हो चुकी है।

(8) प्रदेश में 17 नये एयरपोर्ट के विकास का संकल्प। वर्तमान में 09 एयरपोर्ट से 75 गन्तव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं संचालित। राज्य सरकार द्वारा 12 अन्य एयरपोर्ट (2 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 10 डोमेस्टिक) का विकास। जनपद अयोध्या में राज्य सरकार द्वारा मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम

Scanned with CamScanner

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास।

16. ऊर्जाः

(1) प्रदेश के सभी परिवारों को विद्युत सुलभ कराने के लिए **"पावर फार ऑल"** के तहत अप्रैल 2017 से अब तक 1.43 करोड़ से अधिक घरों का विद्युत संयोजन। ग्रामीण क्षेत्रों में सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,21,324 अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण।

(2) अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु प्रदेश में अब तक कुल 713 नग 33/11 के0वी0 के नये विद्युत उपकेन्द्र स्थापित एवं 1418 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि।

(3) सिंचाई की सुविधा हेतु किसानों को रियायती दर पर 1,68,863 निजी नलकूप का संयोजन। किसानों के लिए अधिकतम भार प्रबन्धन की विद्युत आपूर्ति हेतु 2,227 ग्रामीण फीडरों को अलग किया गया। 1,000 से अधिक आबादी वाले 12,137 ग्रामों/मजरों में खुले तार के स्थान पर 26,805 किमी0 ए0बी0 केबिल लगाकर कार्य पूर्ण किया।

(4) वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु फीडर और वितरण परिवर्तक स्तर पर सिस्टम मीटरिंग हेतु रु0 18,885.24 करोड़ की स्वीकृति तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कुल रु0 16,489.61 करोड़ के कार्य की स्वीकृति।

(5) एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत लगभग 40 लाख विद्युत उपभोक्ताओं ने लाभ प्राप्त किया। विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु 'सम्भव' पोर्टल संचालित, इसमें अभी तक 11,000 से अधिक शिकायतों का हुआ निस्तारण।

(6) सौर ऊर्जा नीति-2017 के तहत वर्ष 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता के सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। इसके तहत निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने पर शतप्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट। निजी क्षेत्र में 1,657 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित तथा 92 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं निर्माणाधीन।

(7) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य विकास योजना के तहत ग्रामों में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु 19,280 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना। पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत प्रदेश के विकास खण्डों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 26,054 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना।

(8) सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामों/मजरों के अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण हेतु 53,354 सोलर संयंत्र स्थापित। प्राथमिक विद्यालयों में 2,727 सोलर आर0ओ0 वॉटर प्लाण्ट स्थापित।

(9) कृषकों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत कृषक को अपनी अनुपजाऊ/बंजर भूमि पर 02 मेगावाट क्षमता तक के सोलर पॉवर प्लाण्ट स्थापना की सुविधा। पी0एम0 कुसुम योजना के अंतर्गत सिंचाई हेतु 19,523 सोलर पम्पों की स्थापना।

(10) प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जैव ऊर्जा नीति-2018 के तहत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं हेतु 2,492 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत।

17. श्रम एवं सेवायोजनः

(1) उ0प्र0 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन। आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर के

Scanned with CamScanner

लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवार्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के निर्देश जारी।

(2) निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता के दृष्टिगत अब तक कुल 4,287 रोजगार मेलों का आयोजन, जिसमें 6,31,502 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(3) बाल श्रम उन्मूलन हेतु 20 जिलों के 1197 ग्राम पंचायतों/शहरी वार्डों में **नया सवेरा योजना** के अन्तर्गत 39,576 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन कर 26,933 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया। 7,561 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित किया गया।

(4) कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 02 लाख रुपये की सहायता। श्रमिकों के कल्याणार्थ 16 योजनाएं संचालित। अब तक 1.12 करोड़ निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण तथा अब तक 1,43,229 निर्माण स्थलों का पंजीकरण।

(5) ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कर्मकारों का 6.66 करोड़ पंजीयन कर उ0प्र0 देशभर में सबसे अधिक पंजीयन कराने वाला प्रदेश बना। भारत सरकार द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र।

(6) श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क/गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना। बाल श्रम विद्या योजना के अंतर्गत 243 बाल श्रमिकों को योजना से आच्छादित किया गया।

(7) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अब तक 6,52,503 लाभार्थियों का पंजीकरण।

18. <u>शिक्षा:</u>

(1) स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश के परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक विद्यालयों, सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा-1 से 08 तक के लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं का नामांकन कर निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही जूता, मोजा, स्वेटर, यूनीफार्म एवं स्कूल बैग हेतु अभिभावकों के बैंक खातों में 2021-22 से धनराशि भेजी जा रही है। 15,000 परिषदीय विद्यालय अंग्रेजी विद्यालय के रूप में चयनित।

(2) आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से विद्यालयों का संतृप्तीकरण कार्य के तहत प्रदेश के 1.29 लाख प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संतृप्त किया गया।

(3) समस्त शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण दीक्षा के माध्यम से आनलाइन उपलब्ध कराया गया। निपुण भारत मिशन को प्रदेश में 04 मुख्य गतिविधियों से एक जन आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है।

(4) भारत सरकार द्वारा माह जून 2021 में जारी परफार्मेंश ग्रेडिंग इन्डेक्स राइटिंग में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग ग्रेड-1 श्रेणी में स्थान प्राप्त।

(5) अरबी एवं फारसी मदरसों तथा परिषद की कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्रों को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराने के उददेश्य से एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम लागू। मेधावी विद्यार्थियों का प्रोत्साहन एवं सम्मान।

(6) प्रदेश में 280 नये राजकीय इण्टर कालेजों/हाईस्कूल का संचालन, 35 नये इण्टर कालेजों,

Scanned with CamScanner

215 राजकीय हाईस्कूल, 77 बालिका छात्रावासों का निर्माण पूर्ण। कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय उ0प्र0 सैनिक स्कूल लखनऊ की क्षमता दोगुनी। इण्टर मीडिएट स्तर पर कम्पार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान। सभी राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जूडो प्रशिक्षण।

(7) असेवित बस्ती के चिन्हीकरण हेतु 'पहुँच पोर्टल', विद्यार्थियों के कैरियर गाइडेन्स हेतु 'पंख पोर्टल', ई-लाइब्रेरी हेतु 'प्रज्ञान पोर्टल', विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण हेतु 'परख पोर्टल', विद्यालयों के वेबपेज/वेबसाइट हेतु 'पहचान' पोर्टल विकसित। राजकीय विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब रेडी स्किल्स के लिए कौशल विकास मिशन के साथ 'प्रवीण योजना' का संचालन। विद्यालयों की संसाधन मैपिंग हेतु 'प्रोजेक्ट अलंकार', राजकीय विद्यालयों में उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक अटेन्डेंस डिवाइस की स्थापना। 39 हाईस्कूल तथा 14 इण्टर कालेज का निर्माण।

(8) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित 26 नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक स्वीकृत। 24 निर्माणाधीन। अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नवीन तकनीकी ज्ञान अर्जित कराने के उद्देश्य से 'यू-राइज' पोर्टल की स्थापना।

(9) ए0के0टी0यू0 के संस्थानों व इंजीनियरिंग कालेजों में स्टार्ट अप नीति के तहत 15 इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना। उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत न्यू एज कोर्स के अंतर्गत डाटा साइन्स एवं मशीन लर्निंग इण्टरनेट आफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रक्रियाधीन।

(10) 03 नये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, 78 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना निर्माण कार्य प्रगति पर, 13 कालेजों में शिक्षण कार्य शुरू। उ0प्र0 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम का प्रख्यापन। जन नायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया हेतु 51 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग के नाम। पाठ्यक्रमों में रोजगार परक पहलुओं का समावेश।

19. <u>समाज कल्याण:</u>

(1) **"मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना"** के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को निःशुल्क साक्षात्कार व ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 21 जुलाई, 2022 तक 5,235 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(2) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 5,98,961 पेंशनरों को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

(3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत अब तक 6,07,648 परिवारों को आर्थिक सहायता।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में कुल 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित।

(5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 913.42 करोड़ रुपये व्यय करते हुए 1,91,224 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। योजना के तहत अनुदान राशि 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई।

(6) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कुल 777.99 करोड़ रुपये से 38,55,530 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर लाभान्वित किया गया। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष

Scanned with CamScanner

2021-22 तक कुल 6,581.75 करोड़ रुपये से 84,69,635 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। पिछड़े वर्ग के गरीबों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कुल 771.03 करोड़ रुपये से 3,85,514 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

(7) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेवल सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कुल 65.34 करोड़ रुपये व्यय करते हुए कुल 72,039 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(8) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए 12 नवीन पेयजल परियोजनाएं पूर्ण, 15 नवीन परियोजनाओं का प्रस्ताव। मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ई-लर्निंग ऐप विकसित।

(9) अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति सुलभ कराने के लिए अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपये की गई। भारत सरकार द्वारा संचालित एवं राज्य पोषित पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत 2021-22 में 13,25,984 छात्र/छात्राएं लाभान्वित। 24 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की आधारभूत संरचना हेतु 5.42 करोड़ रुपये अंतरित।

(10) 11.26 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन तथा 2.56 लाख को उपकरण वितरित।

(11) दिव्यांगजनों के विवाह हेतु 'शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार' योजना, दुकान निर्माण, मोटराइज्ड ट्राई साइकिल योजना, गैर-सरकारी संगठन पंजीकरण व अनुदान योजना का ऑनलाइन संचालन।

20. <u>महिला एवं बाल विकास:</u>

(1) आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा 177 लाख लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरित। **''उत्तम पोषण, उत्तर प्रदेश रोशन''** के टैग लाइन के आधार पर पोषण माह का आयोजन करते हुए जनजागरूकता।

(2) बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु ''मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'' लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी को रु0 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 12.97 लाख पात्र बालिकायें लाभान्वित।

(3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 2.81 लाख गतिविधियों के माध्यम से 1.90 करोड़ महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।

(4) महिला हेल्पलाइन '181' के अंतर्गत 4.84 लाख महिलाओं/बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई।

(5) वन स्टाप सेन्टर योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से अब तक कुल 1.15 लाख मामले संदर्भित किये गये हैं।

(6) मिशन शक्ति अभियान के तहत 8.90 करोड़ पुरुष/महिला/अन्य को जागरूक किया।

(7) पति की मृत्यु से निराश्रित 31.50 लाख महिलाओं को पेंशन देकर लाभान्वित किया गया। पेंशन राशि को रु0 500 से बढ़ाकर रु0 1,000 की गई।

(8) कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) और उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) शुरू की गई, जिसके अंतर्गत क्रमशः 11,049 बच्चों को 4,000 रु0

Scanned with CamScanner

प्रतिमाह और 5,284 बच्चों 2,500 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता सहित उनकी पैत्रक सम्पति की सुरक्षा, उन्हें प्रशिक्षित विशेषज्ञों के माध्यम से ट्रामा काउंसिलिंग आदि सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

21. राजस्व:

(1) रेवेन्यू कोर्ट केस मॉनीटरिंग सिस्टम पोर्टल पर वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था। 300 ग्रामों में कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण।

(2) मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपये दिये जाने के प्राविधान के अन्तर्गत इस वर्ष अब तक 15,896 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के लिए 1,10,313 ग्रामों को अधिसूचित किया गया। अब तक 23,487 ग्रामों के 34,49,017 लाभार्थियों को ग्रामीण आवासीय घरौनी तैयार कराकर वितरित करायी गई।

(3) एंटी भू-माफिया के अन्तर्गत हुये अवैध कब्जे के लिए प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। 64,820.22 हे0 भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया तथा 23,706 राजस्व वाद, 901 सिविल याद व 4,487 एफआईआर दर्ज कराते हुए 742 अतिक्रमण कारियों को भूमाफिया के रूप में चिन्हित करते हुए वैधानिक कार्यवाही।

22. परिवहन:

(1) निगम की 647 जनरथ बसें संचालित तथा प्रदेश के सभी जनपदों को राजधानी से जोड़ा गया।

(2) उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा 150 नई बसों को बस बेड़े में जोड़ने का आदेश जारी।

(3) शादी विवाह, मेले आदि के प्रयोजन हेतु एक सप्ताह की अवधि के लिए स्पेशल परमिट जारी करने में स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था हेतु जून 2022 में पूरे प्रदेश में लागू।

(4) आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स आधारित लर्नर लाइसेंस की व्यवस्था 18 अप्रैल, 2022 से पूरे प्रदेश में लागू।

(5) परिवहन विभाग में पहली बार एकमुश्त शास्ति (दंड) समाधान योजना के लिए अधिसूचना 27 जून, 2022 को जारी। यह तीन माह के लिए प्रभावी रहेगी।

(6)रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2021 में 9.63 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई।

23. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग):

(1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 20,152 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 17,150 किमी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण। 02 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 151 विकास खण्ड मुख्यालयों में 1,324 किलोमीटर हेतु 2199 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां निर्गत, 113 कार्य पूर्ण तथा 26 तहसीलों में 270 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु 391 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां निर्गत, 26 कार्य पूर्ण।

(2) प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु

Scanned with CamScanner

खिलाड़ियों के निवास/ग्राम तक मार्ग का निर्माण/मरम्मत कर **मेजर ध्यान चंद पथ** के रूप में विकसित करने की अभिनव योजना लागू। 21 खिलाड़ियों के निवास/ग्रामों के मार्गों के निर्माण/मरम्मत के कार्य पूर्ण।

(3) प्रदेश के बलिदानी शहीदों के घर/ग्राम तक मार्गों के निर्माण हेतु **'जय हिंद वीर पथ'** योजना के तहत 46 शहीदों के घर/ग्राम तक के 41 मार्गों के निर्माण पूर्ण।

(4) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 189 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण।

(5) 186 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण तथा 72 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू। 537 लघु सेतुओं को पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। इसके अतिरिक्त 291 दीर्घ सेतु, 760 लघु सेतु एवं 140 रेल उपरिगामी सेतु निर्माणाधीन।

(6) **डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना** के तहत प्रदेश के 10वीं व 12वीं कक्षा के (टॉप-20) मेधावी छात्र/छात्राओं के निवास स्थल/स्कूलों तक सड़क निर्माण की योजना संचालित। 298 मार्गों का निर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्ण।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, 10 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का निर्माण तथा औसतन प्रत्येक तीन दिन में एक सेतु का निर्माण पूर्ण किया जा रहा है।

24. <u>पंचायतीराजः</u>

(1) **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में उ0प्र0 प्रथम स्थान पर। प्रदेश के सभी 75 जनपद ओडीएफ घोषित। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में 100 दिवसीय अभियान अवधि में लक्षित 2.41 लाख इज्जत घरों का निर्माण शतप्रतिशत पूर्ण।

(2) सामुदायिक शौचालय निर्माण के तहत ओडीएफ की स्थिरता बनाये रखने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 1,494 सामुदायिक शौचालय कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण।

(3) **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को राज्यों के बीच सामुदायिक स्वच्छता अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर राज्य को पुरस्कार मिला। स्वच्छ सुन्दर सामुदायिक शौचालय में उ0प्र0 को द्वितीय पुरस्कार। कचरा मुक्त भारत में उ0प्र0 को प्रथम स्थान।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई, जिसमें ग्राम प्रधान, सचिव पंचायत, बी0सी0 सखी, महिला बीट सिपाही व अन्य पंचायत स्तर के कर्मी ग्रामीण के विभिन्न कार्यों हेतु उपलब्ध होंगे।

(5) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 में ग्रामों को ओडीएफ प्लस बनाने की दिशा में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन किये जाने हेतु 10,000 ग्रामों में नियोजन, प्रशिक्षण एवं ट्रिगरिंग इत्यादि का कार्य पूर्ण।

25. <u>पर्यटन एवं संस्कृतिः</u>

(1) उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 लागू, जिसके अंतर्गत रुपये 5853.18 करोड़ के निवेश से प्रोजेक्ट स्थापित।

(2) 172 पर्यटन विकास की विभिन्न परियोजनाएं पूरी।

Scanned with CamScanner

(3) ईको एवं रूरल टूरिज्म बोर्ड का गठन। एडवेंचर टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए 03 दिवसीय ब्रज-आगरा रैली का आयोजन।

(4) पर्यटकों को बेहतर आवासीय एवं खानपान की सुविधा हेतु घाटे में चल रहे राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की कार्यवाही प्रगति पर।

(5) हरिद्वार में 100 कक्षों का आधुनिक सुविधायुक्त भव्य भागीरथी अतिथि गृह का लोकार्पण।

(6) आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर 11 से 17 अगस्त, 2022 पर्यटन निगम द्वारा संचालित सभी राही पर्यटक आवास गृहों में श्रद्धालुओं/पर्यटकों से आवासीय किराया मात्र 75 प्रतिशत चार्ज करने का निर्णय।

(7) मथुरा एवं आगरा में पीपीपी मॉडल पर हेलीपोर्ट संचालित करने की प्रक्रिया आरम्भ।

(8) जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन। अयोध्या में प्रतिदिन रामलीला का मंचन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंर्तगत महाराष्ट्र एवं गुजरात से सांस्कृतिक आदान-प्रदान। ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के अंतर्गत 10 ग्रंथों का प्रकाशन। मगहर में संत कबीर अकादमी के विभिन्न भवनों का लोकार्पण। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म दिवस 11 जून के अवसर पर उनके पैतृक जनपद शाहजहांपुर से गोरखपुर तक अमृत यात्रा का आयोजन। महारानी लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस पर झांसी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। श्री गौतम बुद्ध चरित्र ग्रंथ का प्रकाशन। उत्तर प्रदेश के जैन तीर्थंकरों पर पुस्तिकाओं का प्रकाशन। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले कुम्भ के भव्य आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 करोड़ रु0 की व्यवस्था। वाराणसी, कुशीनगर, श्रावस्ती एवं संकिसा में बुद्धिस्ट कॉनक्लेव का आयोजन।

(9) प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर रोप-वे की परियोजना चित्रकूट, अष्टभुजा-कालीकोह (विंध्याचल) एवं बरसाना (मथुरा) में संचालित।

(10) उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ब्रज क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु वर्ष 2022-23 में 60 करोड़ रु0 के प्राविधान के सापेक्ष 11.45 करोड़ की स्वीकृतियां जारी।

(11) प्रयागराज में ओल्ड कर्जन ब्रिज को गंगा गैलरी/हेरीटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु रेलवे की सहमति।

(12) अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर राम की पैड़ी पर 9,41,551 दीप जलाकर एक बार फिर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया। मथुरा में रंगोत्सव एवं कृष्णोत्सव, वाराणसी में शिवरात्रि एवं देव दीपावली का भव्य आयोजन।

(13) वर्ष 2022 में जून तक 7,34,73,189 देशी एवं विदेशी पर्यटक प्रदेश में आये।

26. <u>ग्राम्य विकास, पशुधन व मत्स्य:</u>

(1) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उ0प्र0 में कुल 6.14 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 65 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आच्छादित किया गया है।

(2) ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी0सी0 सखी योजना के अंतर्गत 58,000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से 44,982 बी0सी0 सखी की पद स्थापना।

(3) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अब तक 26.16 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 25.72 लाख आवास पूर्ण।

(4) मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1.08 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य, जिसके

Scanned with CamScanner

सापेक्ष 1.05 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवास पूरा करने में 50प्र0 प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम स्थान पर।

(6) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में भारत सरकार के परफारमेंस इण्डेक्स पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।

(7) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गत वर्षों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

(8) मनरेगा योजना के अंतर्गत विगत 05 वर्षों में प्रदेश द्वारा कुल 3.98 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देते हुए 135.85 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये। योजना मद में रु0 36,309.33 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

(9) प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 20223 तालाबों का चयन किया जा चुका है। 11,204 अमृत सरोवरों का प्राक्कलन बनाते हुए 9,152 पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(10) वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के अंतर्गत 75 नदियों का चयन पुनरूद्धार हेतु किया गया है। 49 जनपदों में 64 नदियों पर पुनरूद्धार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(11) मनरेगा योजना में पंचायती राज विभाग के साथ अभिसरण के अंतर्गत 2954 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(12) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस वर्ष 697 सड़कें, (लगभग 5,500 किमी0) का उच्चीकरण/निर्माण एफ0डी0आई0 तकनीक से करने का लक्ष्य, जिसके सापेक्ष 138 कार्य प्रगति पर।

(13) "मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना" के अन्तर्गत इच्छुक कृषक/पशुपालक/अतिकुपोषित परिवारों को एक-एक गाय व 900 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की योजना। इच्छुक व्यक्तियों को 1.38 लाख गोवंश उपलब्ध कराये गये।

(14) प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 6,222 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 8.55 लाख गोवंश संरक्षित। प्रदेश में चारे एवं भूसे की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए प्रदेश में 3,574 भूसा बैंक स्थापित। 3.26 लाख टन भूसा संरक्षित।

(15) रूरल बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना से अनुसूचित जाति की महिला/पुरूष का चयन कर एक दिवसीय प्रशिक्षण देकर 50 चूजे प्रति लाभार्थी उपलब्ध कराते हुए 15 हजार लोगों को लाभान्वित किया गया।

(16) ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टाधारकों हेतु नई मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू। मछुआ समुदाय व मत्स्य पालकों के उत्थान हेतु नई निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू। मत्स्य पालकों को 2,461.51 लाख गुणवत्तापरक मत्स्य बीज वितरित।

27. <u>वन एवं पर्यावरण:</u>

(1) 35 करोड़ वृक्षारोपण जन आन्दोलन-2022 के अन्तर्गत वन विभाग एवं 26 राजकीय विभागों द्वारा स्वयं व व्यापक जनसहभागिता से 05 जुलाई, 2022 को एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौध रोपित कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करते हुए विश्व कीर्तिमान स्थापित।

(2) भारत की आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर

Scanned with CamScanner

निकायों में 'अमृत वन' की स्थापना। साथ ही नगर वन, खाद्य वन, शक्ति वन, बाल एवं युवा वन, गंगा वन, स्मृति वाटिका, नक्षत्र वाटिका एवं पंचवटी की स्थापना। गोरखपुर के तिलकोनिया रेंज में प्रदेश का पहला आरोग्य वन स्थापित।

(3) प्रदेश के 75 जनपदों में 28 प्रजातियों के वन क्षेत्र के बाहर सामुदायिक भूमि पर 948 वृक्ष विरासत वृक्ष घोषित किये गये।

(4) उत्तर प्रदेश 10 वेटलैण्डस के साथ देश का सर्वाधिक 'रामसर साइट' घोषित राज्य।

(5) पीलीभीत टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में 2014 में बाघों की संख्या 25 थी, जो बढ़कर वर्ष 2018 में 65 हो गई। बाघों की संख्या विगत 05 वर्षों में 118 से बढ़कर 173 हो गई है।

28. <u>खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकासः</u>

(1) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित। महिला एथलीटों के उत्साहवर्धन हेतु रु0 5 लाख दिये जाने की व्यवस्था।

(2) **खेलो इण्डिया योजना** के अन्तर्गत लखनऊ स्थित मऊ-मोहनलालगंज, बस्त-बरगदहिया सूदीपुर, बाराबंकी-धरौली, सोनभद्र-नगांव तथा पीली-सिमरिया महराजपुर के 05 बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा हॉल एवं रनिंग ट्रैक/फील्ड का निर्माण। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 21 बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा हॉल परियोजना स्वीकृत। 41 ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण। 132 खेल मैदान एवं 100 जिम की स्थापना।

(3) जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश राज्य स्पोर्टस यूनीवर्सिटी की स्थापना।

(4) प्रदेश में पंचायत स्तर पर 86,532 युवक/महिला मंगल दल गठित।

(5) कौशल विकास मिशन के अंतर्गत अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित करते हुए 4.50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

29. <u>सूचना विभागः</u>

(1) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक एवं महत्त्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, सोशल मीडिया, फोटो, फिल्म आदि विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(2) सूचना विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0 फिल्म बन्धु/फिल्म विकास परिषद द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर-21 में लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण प्रक्रियाधीन।

(3) लोकभवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार।

(4) कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों तथा कोरोना की रोकथाम हेतु विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा आम जनमानस में जागरूकता लाने का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

30. <u>खादी तथा ग्रामोद्योगः</u>

(1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4,073 इकाइयां स्थापित करते हुए

Scanned with CamScanner

76,684 लोगों को रोजगार।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 13,068 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,54,579 लोगों को रोजगार।

(3) वर्तमान में बिक्री हेतु ऑन लाइन प्लेटफार्म अमेजन पर 83 एवं फ्लिपकार्ट पर 10 खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के उत्पाद उपलब्ध।

(4) देश में **उ0प्र0 प्रथम राज्य है** जहां सौर ऊर्जा आधारित चर्खों के संचालन को मान्यता प्रदान करते हुए अनुदान की सहायता उपलब्ध करायी गयी। 3,832 लाभार्थियों को सोलर चर्खा वितरण कराते हुए 7,664 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया, 8,161 विद्युत चालित कुम्हारी चाक, 747 दोना पत्तल मशीन का वितरण।

(5) मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना अंतर्गत 664.49 लाख का पूंजी निवेश कराते हुए 389 इकाईयों की स्थापना तथा 2,658 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

31. <u>भूतत्व एवं खनिकर्मः</u>

(1) खनिज से संबंधित समस्त सेवाओं को एक छतरी के नीचे लाते हुए **'यूपी माइन मित्रा'** पोर्टल विकसित, जिसके माध्यम से 44,820 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

(2) प्रदेश में उपलब्ध 17 मुख्य खनिज के ब्लॉकों को नीलाम किये जाने की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) बालू/मौरंग के विकल्प के रूप में पत्थर खदानों से निकले रिजेक्ट/ओवरवर्डन से कृत्रिम बालू (एम-सैण्ड) के निर्माण को प्रोत्साहन। इससे राजस्व में होगी वृद्धि।

32. <u>चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणः</u>

(1) प्रदेश में 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की 2,270 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा की 2,200 एम्बुलेंस से करोड़ों मरीजों को परिवहन सेवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

(2) विशेष संचारी रोग नियंत्रण/दस्तक अभियान के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से ए0ई0एस0-जे0ई0 वायरस के रोगथाम हेतु सघन अभियान चलाकर जन जागरूकता। पूर्वांचल क्षेत्र के दिमागी बुखार के कहर से जनता को मिली मुक्ति। इस बीमारी पर 95 प्रतिशत पाया गया नियंत्रण। समुचित प्रबंधन और उपचार के लिए गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल की सभी सिक न्यूबार्न केयर ईकाइयों में वेन्टिलेटर की सुविधा। पूर्ण रूप से सुसज्जित पीआईसीयू, मिनी पीसीआईयू एवं ईटीसी की स्थापना। जे0ई0/सी0एफ0आर0 जैसे वेक्टर जनित रोगों का प्रतिशत शून्य हो गया तथा ए0ई0एस0 13.9 प्रतिशत से घटकर मात्र 1.99 प्रतिशत से भी कम रह गया है।

(3) प्रदेश सरकार ने प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की है।

(4) अयोध्या स्थित देवगॉव में 50 शैय्या के अस्पताल का निर्माण 04 सामुदायिक व 09 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस वर्ष निर्मित।

(5) 2021 में टी0बी0 रोगियों के सफल उपचार की सफलतादर 84 प्रतिशत रही। 01 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2022 तक 2,03,959 से अधिक क्षय रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 37.50 करोड़ रुपये का भुगतान।

Scanned with CamScanner

(6) अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना।

(7) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक जिला एक मेडिकल कालेज की नीति के तहत हर जिले में मेडिकल कालेजों की स्थापना का कार्य गतिमान। अब तक 65 मेडिकल कालेज संचालित, 22 मेडिकल कालेज निर्माणाधीन।

(8) प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की 1,350 सीटों में वृद्धि, पी0जी0 की 725 सीटों में वृद्धि तथा नर्सिंग में 7,000 सीटों एवं पैरामेडिकल में 2,000 सीटों की वृद्धि हुई है।

(9) **'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान** के तहत एक वर्ष में 20 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया गया।

(10) कोविड-19 वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता एवं समय रहते उठाये गये ट्रेस, टेस्ट एवं ट्रीटमेन्ट नीति को पूरी सक्रियता से लागू कर कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया।

(11) उत्तर प्रदेश के कोरोना महामारी के प्रबंधन की केन्द्र सरकार सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की सराहना।

(12) प्रदेश में 541 ऑक्सीजन संयंत्र निर्मित एवं क्रियाशील।

(13) प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव/सुरक्षा के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान तेजी से संचालित। प्रदेश में 01 अगस्त, 2022 तक 34.96 करोड़ से अधिक डोज लोगों को लगायी गई। इतना अधिक वैक्सीनेशन करने वाला उत्तर प्रदेश देश में प्रथम राज्य।

(14) चिकित्सालयों में कोरोना की मुफ्त जांच, दवा, भोजन एवं उपचार।

33. <u>विशेषः निम्नलिखित योजनाओं में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणीः</u>

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत 42 लाख आवास बनाकर उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान।

(2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(3) सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(4) अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 9,41,551 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।

(5) ई-टेन्डरिंग प्रणाली में उ0प्र0 सरकार को सर्वोतम परफार्मेन्स के लिए बेस्ट परफार्मेन्स एयार्ड से सम्मानित।

(6) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान को डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उ0प्र0 पहला राज्य बना।

(7) किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला उ0प्र0 देश का प्रथम राज्य।

(8) दुग्ध उत्पादन में उ0प्र0 देश में प्रथम।

(9) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उ0प्र0 का देश में लगातार प्रथम स्थान।

(10) प्रदेश के 1.70 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने वाला उ0प्र0 देश में प्रथम।

(11) उ0प्र0 चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश में अग्रणी राज्य।

Scanned with CamScanner

(12) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उ०प्र० देश में प्रथम।

(13) मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उ०प्र० प्रथम राज्य।

(14) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उ०प्र० प्रथम राज्य।

(15) ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला उ०प्र० देश का पहला राज्य बना।

(16) पी०एफ०एम०एस० पोर्टल द्वारा डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरित करने में देश में उ०प्र० का प्रथम स्थान।

(17) कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन 34.55 करोड़ डोज लगाने वाला देश में उ०प्र० प्रथम।

(18) 05 एक्सप्रेस-वे बनाने वाला तथा 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाने से उ०प्र० सड़क व हवाई कनेक्टीविटी में सर्वश्रेष्ठ।

(19) ईज आफ डूइंग बिजनेस में उ०प्र० को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त। सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं पारदर्शिता में उ०प्र० अग्रणी राज्य।

(20) औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में उ०प्र० शीर्ष 5 राज्यों में शामिल।

(21) परिवहन निगम को सर्वश्रेष्ठ प्राफिट मेकिंग एस०टी०यू० का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त।

(22) भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत उ०प्र० एस्पायरिंग लीडर के रुप में सम्मानित।

(23) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 35 करोड़ पौधों का रिकार्ड रोपण।

(24) उ०प्र० तिलहन उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान।

(25) मत्स्य उत्पादन में बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत उ०प्र० को 'देश का बेस्ट स्टेट फार इनलैण्ड फिशरीज' घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम स्थान का पुरस्कार।

(26) खाद्य एवं रसद विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर 'एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस-स्टेट श्रेणी में रजत पुरस्कार प्राप्त।

....

Scanned with CamScanner